Mis-statements in prospectus would invite punishment with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to Rs. 5000/- or with both under Section 63(1) of the Act. The question of prescribing stiffer penalties can be considered as and when amendments to Companies Act are moved. Violations, when noticed, are dealt with, as per law.

आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित मामले

2762. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस अधिकरण को कितने मामले प्राप्त हुए और उसके द्वारा कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) सरकार लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान अधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए मामलों की संख्या, क्रमशः 74,748, 78,673 और 82,676 हैं। इन वर्षों के दौरान, निपटाए गए मामलों की संख्या, क्रमशः 45,248, 58,885 और 54,976 हैं।

(ग) अधिकरण के अधिक सदस्यों को एकल सदस्य शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। सदस्यों को ऐसे स्थानों में दौरे पर भेजा जाता है जहां या तो लंबित मामलों की संख्या अधिक है या नियमित न्यायपीठें कार्य नहीं कर रही हैं। शीघ्र निपटारे के लिए, पूर्वोत्तर निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों की संवीक्षा की जाती है। समान विधायकों वाली अपीलों की सुनवाई के लिए एक समूह में रखा जा रहा है।

2763. [Transferred to 25th March, 1991.]

Assets of 20 large Industrial Houses

2764. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the assets, turnover before and after income-tax, and profit and loss as shown in their overall balance sheets by the first 20 large industrial houses as per latest information available with his Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): A statement (*see* below) showing the latest available data on Assets, Total Income (including Turnover) and Profit Before Tax in 1989-90 (accounting year ending April, 1989-March, 1990) of Companies registered under Section 26 of the MRTP Act and belonging to the first 20 large Industrial Houses ranked according to their assets in 1989-90 is annexed.

Statement

Statement showing the Assets, Total Income (including Trunover) and Profit Before Tax in 1989-90 (Accounting year ending April, 1989 March, 1990) of Companies Registered under section 26 of the MRTP Act and belonging to the first 20 large Industrial houses ranked according to their Assets in 1989-90.

(Rs. in crores)

Sl. No.	Industrial House	Assets	Total Income (including Turnover)	Profit before Tax
1	Tata	8530.93	8079.80	594.42
2	Birla	8473.35	8417.41	439.55
3	Reliance	3600.27	1901.11	87.36
4	Thapar	2177.15	2280.59	109.78
5	J.K. Singhania	2139.00	1786.93	35.74
6	Larsen & Toubro	1681.52	1128.26	62.47
7	Modi	1399.37	2009.35	23.09

(Rs. in crores)

Sl. No.	Industrial House	Assets	Total Income (including Turnover)	Profit before Tax
8	Bajaj	1391.06	1907.87	133.88
9	Mafatlal	1343.55	1765.84	85.58
10	M.A. Chidambaram	1273.35	1161.47	38.78
11	Hindustan Lever	1209.46	2396.60	203.73
12	United Breweries*	1189.24	1227.50	36.63
13	T.V.S. Iyenger	1177.10	1388.41	59.80
14	I.T.C.	965.13	2749.70	122.88
15	Shri Ram	933.93	1445.40	20.99
16	A.C.C.	902.72	1223.38	2.07
17	Oswal Agro	870.34	417.33	35.75
18	Mahindra & Mahindra	773.55	1022.45	20.07
19	Essar	756.49	244.35	34.82
20	Kirloskar	735.51	985.46	45.36

NOTE: *The figures for United Breweries Industrial house at Sl. No. 12 include those of the erstwhile Best & Crompton' Industrial House of 1988-89.

उर्दू में उपलब्ध कानून की पुस्तकें

2765. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी**: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानून की उर्दू में उपलब्ध पुस्तकों के क्या नाम हैं और उनको कहां से प्राप्त किया जा सकता है; और

(ख) कानून की महत्वपूर्ण पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद कराने और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) सरकार को उर्दू में प्रकाशित विधि पुस्तकों के नाम और उनकी उपलब्धता के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार के पास इस समय, प्राइवेट व्यक्तियों या संगठनों से उर्दू में विधि पुस्तकों का अनुवाद कराकर उपलब्ध कराने के लिए कोई स्कीम नहीं है। तथापि, विधि मंत्रालय का विधायी विभाग, राज्यों की राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों और विनियमों के अनुवाद के लिए जिम्मेदार है। इसने अन्य भाषाओं के साथ उर्दू में भारत के संविधान का अनुवाद कराकर प्रकाशित किया है।

Registered Companies of West Bengal

2766. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names and details of companies that are registered with the Registrar of Companies, West Bengal, Calcutta in which multi-nationals or groups of foreigners have had shareholdings along with the composition of their Boards of Directors, percentage of shareholdings by foreigners in each such companies;

(b) whether some such companies are also registered as Private Limited companies within the meaning of Companies Act, 56;

(c) whether a few of them have been operating ships and vessels for carrying Indian and foreigner cargos; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): (a) and (b) There are about 35,000 companies